सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ` 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया: अखिलेश यादव

कानपुर,बुधवार , 17 सितंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 244, पृष्ठः 8+4

इनसाइड रेलवे आउटर पर चल रहा डीजल चोरी का धंधा बेनकाब » Pg3

» Pg10

अडिग ऊर्जा के साथ दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी

» दुनिया के ताकतवर नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी आज 75 वर्ष के हो गए

» पूरे देश में मनाया जा रहा पीएम मोदी का जन्म दिन

जॉर्जिया की प्रधानमंत्री ने सेल्फी की फोटो जारी कर दी बधाई

पूरे दुनियां से आए बधाई संदेश

नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर देश-विदेश से नेता और प्रमुख हस्तियों उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. विशेष रूप से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शुभकामनाओं ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को रेखांकित किया है. इन बधाइयों में न केवल व्यक्तिगत स्नेह व्यक्त हुआ, बल्कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई.

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा कर लिखा, %भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपकी ताकत, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता एक प्रेरणा स्रोत है. मित्रता और सम्मान के साथ, मैं आपको स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि आप भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाते रहें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सके

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

नई दिल्ली।भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी आज 75 वर्ष के हो गए। यह अवसर केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति और वैश्विक परिदृश्य में हुए बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। साधारण परिवार से निकलकर विश्व मंच पर सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार होने तक मोदी की यात्रा अभूतपूर्व मानी जाती है।17 सितम्बर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी का जीवन संघर्ष और आत्मविश्वास का उदाहरण रहा। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राष्ट्रभक्ति और अनुशासन के संस्कार पाए। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें राजनीति के शिखर तक ले गए।

2001 में गुजरात की सत्ता संभालने के बाद मोदी ने विकास और उद्योगोन्मुख नीतियों से पहचान बनाई। हालांकि 2002 के दंगे उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद बने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी और जनता के बीच अपनी पकड़ और मजबूत की।2014 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया और देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद से अब तक उन्होंने राजनीति की दिशा और स्वरूप को बदल डाला। 'जनधन योजना', 'उज्ज्वला योजना', 'आयुष्मान भारत', 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें गरीबों और मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाया। विदेश नीति में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर नया आयाम दिया।

मोदी के कार्यकाल में कई बड़े और विवादास्पद फैसले भी सामने आए — नोटबंदी, कृषि कानून, नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे कदमों ने उन्हें राजनीतिक बहसों के केंद्र में रखा। आलोचनाओं के बावजूद उनकी जनस्वीकृति बनी रही।

करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं मोदी

आज मोदी न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। वैश्विक मंचों पर उनकी उपस्थिति, राष्ट्रवाद से जुड़े उनके संदेश और 'विकास एवं आत्मनिर्भर भारत' का उनका दृष्टिकोण उन्हें अलग पहचान दिलाता है।पचहत्तर वर्ष की उम्र में भी नरेंद्र मोदी जिस तरह से सक्रिय, ऊर्जावान और संवादशील बने हुए हैं, वह करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

समर्थक उन्हें नए भारत के निर्माता मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें केंद्रीकृत सत्ता का चेहरा कहते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि मोदी ने भारतीय राजनीति की धारा को नई दिशा दी है और उनका प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाता रहेगा।

पीएम के जन्मदिन पर लखनऊ में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ

लखनऊ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज लखनऊ में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार फवंचित को वरीयता का मंत्र धरातल पर उतरा है। इसी दृष्टिकोण ने बीते 11 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद की है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित और वंचित सभी को प्राथमिकता देकर प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है।उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में फविरासत का

सम्मान केवल एक घोषणा नहीं बल्कि धरातल पर उतरी सच्चाई है।उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई ?

भाजपा नेता बोले- बिल्डर से 9 करोड़ वसूले, अखिलेश दुबे है मास्टरमाइंड

» भाजपा नेता मनोज सिंह बोले झूठे मुकदमे और रंगदारी वसूली का मास्टरमाइंड है अखिलेश दुबे

» किदवई नगर थाने में डकैती,अपहरण समेत गंभीर धाराओं में फर्जी केस दर्ज कराने का आरोप

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

भाजपा नेता मनोज सिंह

अखिलेश दुबे/अवनीश दीक्षित

कानपुर। भाजपा नेता व अधिवक्ता मनोज सिंह ने मंगलवार को कुख्यात अखिलेश दुबे और उसके गिरोह पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुबे ने नोएडा के एक बड़े बिल्डर को रंगदारी के जाल में फंसाया और किदवई नगर थाने में डकैती, अपहरण व हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने बिल्डर को उठाकर हिरासत में लिया और जब तक 9 करोड़ रुपये की मोटी रकम नहीं मिली, तब तक उसे छोड़ा नहीं गया।

मनोज सिंह ने बताया कि अखिलेश दुबे ने उनके प्लॉट पर कब्जा करने के लिए भी कई हथकंडे अपनाए थे। जब इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसने उन पर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन जांच में हर बार उसके आरोप बेबुनियाद साबित हुए और अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

इसके बावजूद दुबे और उसका गिरोह लगातार धमकियां देता रहा और रुपयों की मांग करता रहा।उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है।

दुबे ने झूठे मुकदमों के जरिए रंगदारी वसूली और लोगों का चरित्र हरण करने का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है। भाजपा नेता ने यह भी बताया कि किदवई नगर थाने में दर्ज मुकदमे में गुरुग्राम निवासी विनीत कुमार शर्मा को वादी बनाकर बिल्डर दिनेश पांडेय और उनके सहयोगियों पर बलवा, मारपीट, लूट, अपहरण और जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया। लेकिन पुलिस की जांच में न तो घटना की पुष्टि हुई और न ही कथित वादी ही मिला।

मनोज सिंह का कहना है कि अखिलेश दुबे का आतंक और रंगदारी का खेल अब खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की पुन- जांच हो ताकि सच सामने आ सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

एटीएम बदलकर ठगी करने वाला अंतरराज्यीय गैंग दबोचा

» किदवई नगर पुलिस ने साकेत नगर एटीएम से पकड़े तीन शातिर ठग

» छह साल से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बना रहे थे निशाना

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। किदवई नगर पुलिस ने रविवार को एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गाजियाबाद, हरदोई और लोनी के रहने वाले तीन शातिर ठगों को साकेत नगर स्थित एक्सिस बैंक एटीएम से रेकी करते हुए रंगेहाथ दबोच लिया। आरोपितों के पास से विभिन्न बैंकों के 43 एटीएम कार्ड, 22 हजार रुपये नकद और दो तमंचे बरामद हुए हैं।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि गिरोह के सरगना ईशानू खान उर्फ भोला (गाजियाबाद), अरुण कनौजिया (हरदोई) और सर्वेश राजपूत उर्फ विक्की (लोनी देहात) लंबे समय से एटीएम बदलकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपित पहले एटीएम में घुसने वाले शख्स का पिनकोड चोरी-छिपे देख लेते थे और फिर मौका पाकर उसका कार्ड बदल देते थे। इसके बाद उनके साथी उसी कार्ड से पीड़ित के खाते से रुपये निकाल लेते थे।पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह पिछले छह साल से बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को आसान शिकार बनाकर लाखों की ठगी कर चुका है। गिरोह के दो सदस्य अरुण और सर्वेश पहले भी दिल्ली, गाजियाबाद और कानपुर की जेल जा चुके हैं। अरुण पर पांच और सर्वेश पर आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।रविवार को जब औरैया पुलिस ने टोल प्लाजा पर आरोपितों की कार रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बूम तोड़कर भागने का प्रयास किया। उनकी कार पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद सभी भाग निकले। तलाशी में कार से भी 43 एटीएम कार्ड मिले थे। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि ठगी के बाद वह एटीएम कार्ड फेंकते नहीं थे, बल्कि उन्हें बार-बार नए शिकार फंसाने में इस्तेमाल करते थे।

मंजुल आईटीआई में बृहद रोजगार मेला आयोजित

» 150 छात्रों का कंपनियों ने किया चयन

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।मंजुल आईटीआई, मेहरबान सिंह का पुरवा, कानपुर नगर में मंगलवार को देश के विशिष्ट प्रतिष्ठानों द्वारा बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड (कानपुर नगर), रिलायंस इंडस्ट्रीज (जामनगर, गुजरात), गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड (हरियाणा) सहित कई नामी कंपनियों ने शिरकत की।रोजगार मेले में लगभग 250 से 300 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से लगभग 150 छात्रों का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। चयनित छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार 15,000 से 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की पेशकश की गई। संस्थान के प्रधानाचार्य एस. एन. दुबे ने बताया कि यह रोजगार मेला छात्रों के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ और उन्हें उद्योग जगत से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इस मौके पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज आशुतोष कुमार, ग्रुप इंस्ट्रक्टर मयंक दुबे, शिवानी साहू, रिया सिंह, स्वाति सविता तथा कंपनियों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

कटरी के एक हजार किसानों की 150 हेक्टेयर फसल बर्बाद

कानपुर। गंगा बैराज के आसपास बसे आठ गांवों में बाढ़ से एक हजार से अधिक किसानों की सब्जी व बागवानी की फसलें बर्बाद हो गईं। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित किसानों की जमीन का सर्वे कराया तो हकीकत सामने आई। जल्द ही सभी को मुआवजा राशि दी जाएगी। मंगलवार को एसडीएम सदर अनुभव और तहसीलदार विनय कुमार ने पीड़ितों के बीच पहुंचकर राशन किट वितरित की। बीते 20 दिन से गंगा बैराज किनारे स्थित एक दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया था। लोगों के घरों में पानी भर गया था। 800 से अधिक परेशान परिवारों ने दूसरी जगह आश्रय लिया था। जिला प्रशासन ने ख्योरा कटरी, ईश्वरीगंज, चिरांद, प्रतापपुर हरी, सिंहपुर, हृदयपुर, पृथ्वीगंज, कटरी लक्ष्मी खेड़ा गांवों की जमीनों का सर्वे किया। करीब एक हजार किसानों की 150.54 हेक्टेयर फसल प्रभावित मिली है।

रेलवे आउटर पर चल रहा डीजल चोरी का धंधा बेनकाब

» रेलवे लाइन से डीजल चोरी कर नदी के रास्ते सप्लाई

» स्वराज इंडिया की पड़ताल में सामने आया डीजल चोरी का संगठित गिरोह

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। डीजल और पेट्रोल चोरी का काला कारोबार लंबे समय से चल रहा है। स्वराज इंडिया अखबार ने इस मामले में लगातार खुलासे किए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कई डीजल चोर जेल भी भेजे गए। इस गैंग का सबसे बड़ा नाम देशराज उर्फ टेशू सामने आया था। अब स्वराज इंडिया की पड़ताल में एक और सक्रिय गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें संदीप गौतम, लायक ठाकुर, प्रांशु गौतम और समीर गौतम मुख्य रूप से शामिल हैं।

डीजल तस्करों का सक्रिय गिरोह

ये गिरोह कानपुर से दिल्ली रूट पर पनकी और सचेंडी थाना क्षेत्र के बीच रेलवे आउटर पर खड़ी मालगाड़ियों से डीजल चोरी करता है। पूरी योजना बेहद सुनियोजित होती है गैंग के सदस्य पहले मालगाड़ी की टंकी से डीजल निकालकर कट्टों में भरते हैं और उन्हें रेलवे लाइन के नीचे बह रही नदी में फेंक देते हैं।

बाद में वही ड्रम पानी से निकालकर सप्लाई की जाती है। खबर में शामिल एक तस्वीर में साफ दिख रहा है कि किस तरह आरोपी प्रांशु गौतम नदी से डीजल से भरे कट्टे बाहर निकाल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे खेल में आरपीएफ और रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गार्ड भी इन आपराधिक तत्वों से मिले रहते हैं। स्वराज इंडिया की टीम ने पहले भी ग्राउंड जीरो पर जाकर दूर से इन गतिविधियों का वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन तब चेहरा सामने नहीं आया था। अब लंबे समय की पड़ताल और जांच के बाद गिरोह के असली चेहरे उजागर हो गए हैं।

इन अपराधियों के पास अवैध असलहे भी रहते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति यदि मौके पर जाकर विरोध करने की कोशिश करे तो उसके साथ हमला होने की आशंका रहती है। यही वजह रही कि स्वराज इंडिया की टीम ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चोरी की घटनाओं को दूर से रिकॉर्ड किया। टीम का मकसद था कि सच उजागर हो और अपराधियों की गोली पत्रकारों तक न पहुंचे।

हाउस टैक्स में मनमानी के खिलाफ युवा व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स का सही आकलन न होने और मनमाने ढंग से बढ़े हुए बिल भेजे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल रजि. कानपुर महानगर ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश प्रभारी एवं महानगर अध्यक्ष कपिल सब्बरवाल के नेतृत्व में व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त सुधीर कुमार से मुलाकात कर यह ज्ञापन कैंप कार्यालय में सौंपा। व्यापार मंडल ने कहा कि नगर निगम द्वारा बिना वास्तविक आकलन के हाउस टैक्स के बढ़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं और उनकी वसूली का फरमान थमाया जा रहा है। इससे व्यापारियों और आम नागरिकों में आक्रोश है।

व्यापार मंडल ने मांग की कि इस समस्या का तत्काल समाधान करते हुए सही आकलन के बाद ही टैक्स निर्धारण किया जाए। इसके साथ ही बाजारों में व्यापारी संगठनों के माध्यम से हाउस टैक्स सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं।

नगर आयुक्त ने व्यापार मंडल को आश्वासन दिया कि कैंप लगाकर टैक्स का सही निर्धारण कराया जाएगा और व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर होगा।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रणजीत सिंह बिल्लू, अजय सराफ, सौरभ गुप्ता, मिकी मनचंदा, रणजीत सिंह, बब्बू अवनीत सिंह, राहुल गुप्ता, नितिन छाबड़ा, सौरभ गोसाई, हरप्रीत सिंह, सोनू बग्गा, परमजीत सिंह, पिंचू राकेश भाटिया, उमेश भाटिया, इंद्रपाल लवली, अंकुर गुप्ता, मोहित सेठ सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

सेंट्रल स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, प्रबंधक बोले- स्वच्छ रेलवे सुरक्षित यात्रा की गारंटी है

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई, जिसमें रेलवे कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि स्वच्छ रेलवे सुरक्षित यात्रा की गारंटी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार को स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ला ने रेल कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ रेलवे ही सुरक्षित और सुखद यात्रा की गारंटी है।

उन्होंने कहा कि रेलवे की स्वच्छता केवल विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक दायित्व है। हर कर्मचारी व हर यात्री इसके ब्रांड एंबेसडर हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने, यात्रियों को जागरूक करने और अभियान को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया।

बाढ़ पीडितों को 'मरहम' लगा रहा जिला प्रशासन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» एसडीएम सदर ने बाढ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, पीडितों को राशन किट विरतण

कानपुर।बाढ पीडितों के लिए शासन की ओर से लगातार सहायता मुहैया करायी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों का प्रशासनिक अफसरों ने स्थलीय निरीक्षण किया। गंगा बैराज मार्ग पर अस्थायी रूप से निवास कर रहे प्रभावित परिवारों का अधिकांश हिस्सा अपने घरों को लौट चुका है तथा शेष प्रभावित व्यक्तियों ने भी कल तक वापस जाने की सहमति व्यक्त की है।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेटझ्र एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने लोगों से बात कर उनसे परेशानी पूछी।

इस दौरान तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी ने प्रभावित फसल क्षति की जानकारी कर्मचारियों से प्राप्त की। यहां राशन किट का वितरण किया गया। एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, लोगों से उनके परेशानी संबंधित जानकारी ली गई है।

तहसील के कर्मचारी मौके पर कार्य कर रहे हैं। जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उनको मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

राजस्व अफसरों ने ग्राम पंचायत कटरी ख्योरा अंतर्गत ग्राम भगवानदीनपुरवा, भोपालपुरवा, बनियापुरवा, दुर्गापुरवा, लक्ष्मणपुरवा, गिल्लीपुरवा (कटरी ख्योरा) तथा बड़ा रामपुर मजरा कटरी शंकरपुर सराय में पात्र लाभार्थियों को राशन किट का वितरण किया।

तहसीलदार सदर ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित फसल क्षति का आंकलन भी पूर्ण कर लिया गया है। इसमें लगभग 1000 कृषक तथा 150.54 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रभावित पाया गया है। प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिए जाने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है।

राशन किट में शामिल आइटम

प्रत्येक किट में खाद्यान्न (आलू, आटा, चावल, दाल, चना, चीनी, नमक, तेल आदि) के साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ (साबुन, माचिस, मोमबत्ती, तौलिया, सैनिटरी पैड, ढक्कनदार बाल्टी, तिरपाल, सूती कपड़ा, डिस्पोजल बैग एवं डिटॉल/सेवलॉन) सम्मिलित की गई हैं।

खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों को नोटिस

» उपायुक्त उद्योग एवं जिला आबकारी अधिकारी को शोकॉज़ नोटिस

» अच्छा कार्य न करने वाले लेखपालों की सूची बनाने का आदेश

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।जिलाधिकारी ने लगातार डी श्रेणी लाने पर उपायुक्त उद्योग एवं जिला आबकारी अधिकारी को शोकॉज़ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को दिए हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम (अर्बन) प्रवीण यादव बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त स्ष्रूको कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अपनी-अपनी तहसीलों में अच्छा कार्य न करने वाले लेखपालों की सूची तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करें।

साथ ही, जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वसूली में सुधार नहीं लाया गया तो अक्टूबर माह में उनके विरुद्ध शासन को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने तथा वसूली में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),ष्टरू (आपूर्ति), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

मेडिकल कॉलेज के बाहर दो छात्र गुटों में मारपीट

तीन के सिर फटे...पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उन्नाव। उन्नाव जिले में सोहरामऊ क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज में मंगलवार की दोपहर वाहन पार्किंग को लेकर विवाद के बाद शाम सात बजे कॉलेज के बाहर दो छात्र गुटों में मारपीट हो गई। हमलावरों ने धारदार हथियार और ईंट से हमला कर दिया। इसमें तीन छात्रों के सिर भी फूटे। पीड़ित छात्रों ने थाने में तहरीर दी है। हसनगंज सीओ ने घटना की जांच की और मारपीट करने वाले तीन आरोपी छात्रों को थाने में बैठाया है।

उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है।लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सोहरामऊ थाना क्षेत्र में स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज के 2021 बैच के एमबीबीएस छात्रों में महाराष्ट्र के जिला नलगांव थाना सावदा के तालुका रावेर निवासी विक्रांत चौधरी पुत्र हेमंतधर्म चौधरी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि वह साथी महाराष्ट्र के जिला लातूर थाना शिवजी नगर निवासी जयेश धालगढ़े और राजस्थान के जिला दौसा के मंडावर निवासी सुगम सैनी के साथ भल्लाफार्म तिराहे पर स्थित दुकान पर मंगलवार शाम को चाय पीने गया था। लौटते समय कॉलेज से पहले एमबीबीएस 2022 बैच के सात छात्रों ने रोक लिया और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। इससे तीनों के सिर फूटे और धारदार हथियारों से हमले की भी गंभीर चोटें आई हैं। विक्रांत ने बताया शाम चार बजे 2022 बैच के छात्रों की 2019 बैच के छात्रों से कैंपस में गाड़ी खड़ी करने को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन उस घटना में वह तीनों (विक्रांत, जयेश और सुगम सैनी) शामिल नहीं थे और ना ही उनके किसी तरह का कोई विवाद हुआ था।

आरोपी तीन छात्रों से थाने में पूछताछ

इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई। सूचना पर सीओ हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया सोहरामऊ थाने पहुंचे और दोनों पक्षों के छात्रों से बात की। सीओ ने बताया कि जिस स्थान पर मारपीट हुई वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। फुटेज निकलवाई जा रही है। मारपीट करने वालों की पहचान कर सभी पर जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन को भी मारपीट करने वाले छात्रों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। हमले के आरोपी तीन छात्रों से थाने में पूछताछ की जा रही है।

सम्पादकीय

दुनिया के विपरीत भारत में बेटा अनुराग

देशकाल-परिस्थितियों और बदलती जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर एक सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बदलाव लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में आ रहे परिवर्तन का है। जैसा कि हाल ही में 'द इकनॉमिस्ट' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। दुनियाभर में, अतिरिक्त पुरुष जन्म की संख्या- जो वर्ष 2000 में 1.7 मिलियन तक अधिक थी, साल 2025 तक लगभग दो लाख तक गिर गई है। निस्संदेह, यह प्रजनन विकल्पों में एक अप्रत्याशित बदलावों का संकेत है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या हैज दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती जा रही है। बल्कि कई देशों में तो महिलाओं की बैचलर डिग्री की संख्या तक पुरुषों की तुलना में अधिक है। पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं।वहीं भारत में परिस्थितियां एक जटिल तसवीर प्रस्तुत करती हैं। यूं तो सदियों से भारत का समाज पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है। लेकिन लिंग चयन के लिये किए जाने वाले गर्भपात पर शासन व प्रशासन की कानूनी सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद परंपरागत रूप से समाज में गहरी जड़ें जमाने वाला बेटा मोह अब भी प्राथमिकता बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा,पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा, भारत में बेटी वरीयता, जहां यह मौजूद है, अक्सर सशर्त होती है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए। भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता-पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं। परंपरावादी समाज में यह धारणा बलवती रही है कि बेटियां दूसरे परिवार की हैं। यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में लड़कियां हाशिये पर रख जाती हैं।

ट्रंप के दावों के बावजूद रुकेगा नहीं ईरान

पुष्परंजन

क्या ट्रम्प के 'सीज़ फ़ायर' बोल भर देने से शांति हो जायेगी? इस सच से अमेरिकन्स वाकिफ हैं कि अकेला ईरान है, जिसके 'हमास', 'हिज्बुल्लाह', 'इस्लामिक जिहाद' जैसे प्रॉक्सी मिलिटेंट्स, पूरे मिडल ईस्ट में पसरे हुए हैं।आप ईरान के ठिकानों पर कोऑर्डिनेटेड बमबारी करें, फिर घोषणा कर दें, कि इस्राइल-ईरान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। यह अमेरिकी दादागिरी का दीगर रूप है। खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 'ट्रुथ सोशल' पर डोनाल्ड ट्रम्प बोले, 'यदि ईरान के पास परमाणु हथियार है, तो आप शांति नहीं पा सकते।' ऐसे बोल-वचन इसलिए, ताकि पश्चिमी देश खुश हो जाएं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य और नैतिक रूप से उचित साबित हो। ये वही ट्रम्प हैं, जो बात-बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में दावत देते हैं। लेकिन, तोताचश्म पाकिस्तान ने बयान दिया, कि हम ईरान के साथ खड़े हैं।

अगर, परमाणु क्षमता का आकांक्षी ईरान शांति का दुश्मन है, तो अमेरिका के पास लगभग 5,244 परमाणु हथियार हैं, जो कि इस्राइल के अघोषित शस्त्रागार में अनुमानित संख्या से दस गुना अधिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अधिकरण (आईएइए) खुफिया के अनुसार, 'ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार नहीं बनाया है।' ईरान परमाणु हथियारों के अप्रसार (एनपीटी) पर संधि का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है। इजरायल नहीं है।अमेरिका के पास 100 से अधिक देशों में 800 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। इसकी तुलना चीन से करें, जो पड़ोसी क्षेत्रों में केवल एक विदेशी सैन्य अड्डे रखता है, या रूस, जो लगभग बीस सैन्य अड्डों का प्रबंधन करता है। यह वैश्विक स्थिरता का संकेत नहीं है। यह एक साम्राज्यवादी ढब है। पूरी दुनिया का चौधरी बने रहने की लिप्सा। विदेश संबंध परिषद के अनुसार, 'इस समय मध्य पूर्व में कम से कम 19 अमेरिकी मिलिटरी बेस हैं। इनमें से आठ स्थायी सैन्य ठिकाने हैं।' बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बनाए अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटवाने की हिम्मत वहां की कठपुतली सरकारें नहीं करतीं। अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में लगभग 40,000 सैनिक तैनात किये हैं।

क़तर में 1996 में निर्मित अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। यह ईरान द्वारा लक्षित स्थलों में से एक था। इस बेस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का क्षेत्रीय मुख्यालय है, जहां 11,000 से अधिक अमेरिकी और गठबंधन सेना के सदस्य रहते हैं। यहां जो कुछ ईरानी हमला हुआ, ट्रम्प ने उसका मखौल उड़ाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े की तैनाती है, जिसमें लगभग 9,000 सैन्य कर्मी और नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। 3 जनवरी, 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के प्रतिशोध में अल-असद और एरबिल अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया था।

वर्ष 2023 से ईरान समर्थित हौथी आतंकवादी समूह लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। इराक में तेहरान समर्थित शिया मिलिशिया, हिजबुल्लाह अलग से एक्टिव हैं। तो क्या ट्रम्प के 'सीज़ फ़ायर' बोल भर देने से बंदूकें गरजनी बंद हो जायेंगी? इस सच से अमेरिकन्स और इस्राइली वाकिफ हैं कि अकेला ईरान है, जिसके 'हमास', 'हिज्बुल्लाह', 'इस्लामिक जिहाद' जैसे प्रॉक्सी मिलिटेंट्स, पूरे मिडल ईस्ट में पसरे हुए हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख 'स्विंग स्टेट' कूटनीतिक समाधान की कोशिश में हैं। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, जॉर्डन सहित अधिकांश अरब राज्यों ने ईरान पर इस्राइल के हमलों की निंदा की है, ताकि तेहरान को इन पर भरोसा हो। ट्रम्प ने ऐसी प्रतिक्रिया सोची नहीं थी। युद्धविराम की तत्काल घोषणा की सबसे बड़ी वजह यह भी है।ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि हुसैन शरीयतमादारी ने कट्टरपंथी कायहान अखबार से कहा, 'अब हमारी बारी है। हम बिना समय बर्बाद किए।

कड़वाहट से मुक्ति के लिये सम्मानजनक अलगाव

नो फाल्ट तलाक

डा0 सुधीर कुमार

शिल्पा बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, 'अपरिवर्तनीय वैवाहिक विच्छेद' के आधार पर सीधे तलाक को मंजूरी दी थी। इसे 'नो-फॉल्ट' सिद्धांत की दिशा में एक बड़ा और प्रगतिशील कदम माना गया।आज के बदलते सामाजिक परिवेश में, जहां रिश्ते जटिल होते जा रहे हैं, तलाक एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारत में तलाक की प्रक्रिया अक्सर लंबी, तनावपूर्ण और आरोप-प्रत्यारोप से भरी होती है।

यह न केवल पति-पत्नी बल्कि उनके बच्चों और परिवारों के लिए भी भावनात्मक और आर्थिक बोझ बन जाती है। पारंपरिक तलाक कानूनों में, तलाक तभी दिया जाता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर 'गलती' (जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग) साबित करे। इसमें अक्सर एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई शामिल होती है, जिसमें दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने पड़ते हैं, जिससे कड़वाहट और दुश्मनी बढ़ती है।इसके विपरीत, 'नो-फॉल्ट' तलाक में, तलाक के लिए किसी भी पक्ष को दूसरे की गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बेवफाई, क्रूरता या परित्याग जैसे विशिष्ट कारणों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो दोनों पक्षों को सम्मानपूर्वक अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मुख्य आधार 'अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका विवाह' होता है। ऐसे में, विकसित

देशों के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां 'नो-फॉल्ट' तलाक एक सफल मॉडल साबित हुआ है।विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में 'नो-फॉल्ट' तलाक ने कई सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। सबसे पहले, इसने तलाक की प्रक्रिया को काफी सरल और तेज बना दिया है। अदालती कार्यवाही कम होती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। दूसरा, यह प्रक्रिया को कम विरोधी बनाता है। जब किसी एक पक्ष पर दोष नहीं लगाया जाता, तो कटुता और प्रतिशोध की भावना कम होती है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनता है और भविष्य में सह-पालन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यह महिलाओं को सशक्त बनाता है। पारंपरिक तलाक कानूनों में अक्सर महिलाओं को अपनी स्थिति साबित करने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन 'नो-फॉल्ट' तलाक उन्हें इस बोझ से मुक्त करता है।भारत में वर्तमान में तलाक के लिए विभिन्न आधार उपलब्ध हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक (धारा 13 बी) शामिल हैं। आपसी सहमति से तलाक 'नो-फॉल्ट' सिद्धांत के करीब है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें और प्रतीक्षा अवधि शामिल है। भारत में तलाक से संबंधित मौजूदा कानून, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, अभी भी काफी हद तक 'फॉल्ट-आधारित' है। जबकि आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है, यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष सहमत हों और एक निश्चित अवधि तक अलग रह चुके हों। लेकिन अगर एक पक्ष तलाक नहीं चाहता, तो दूसरे पक्ष को क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग या मानसिक बीमारी जैसे आधारों पर दोष साबित करना पड़ता है। यह प्रक्रिया अक्सर अपमानजनक और लंबी खींचने वाली होती है, जिससे दोनों पक्षों को मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। इस महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'अपरिवर्तनीय वैवाहिक विच्छेद' के आधार पर है।

सीधे तलाक को मंजूरी दी।

इरफान बोले- कानपुर वालों की दुआ

जो पत्नी को विधायक बनाया, कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। पेशी पर ले जाते समय जब इरफान ने अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। उनकी हाथ पकड़ने को लेकर पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। बोले मेरा बेटा है...क्या मिल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कानपुर वालों की दुआ है, जो पत्नी को विधायक बनाया। यह बातें सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कोर्ट में पेशी पर जाने से पहले कहीं। आगजनी के मुकदमे में सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बुधवार को कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। लगभग एक साल बाद इरफान को कानपुर लाया गया।

इससे पहले पिछले साल अगस्त में वह कानपुर आए थे। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर के मुकदमे में आरोप तय होने हैं। मुकदमे में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज और मुर्सलीन खान उर्फ भोलू आरोपी हैं। इसमें इरफान के अलावा रिजवान और इसराइल कानपुर जेल में बंद हैं जबकि बाकी को जमानत मिल चुकी है।

स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाना था

इरफान को महाराजगंज जेल से 10 सितंबर को ही कोर्ट में पेश होना था, लेकिन जेल से आई रिपोर्ट में कहा गया था कि इरफान को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाना है। इसलिए कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। पेशी के लिए किसी अन्य तारीख की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख दे दी थी।

गैंगस्टर के मुकदमे में नहीं मिली है जमानत

जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने अपने घर में आगजनी के मामले में जाजमऊ थाने में नवंबर 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें सेशन कोर्ट ने सात जून 2024 को इरफान व उसके भाई रिजवान समेत पांच लोगों को सात-सात साल कैद की सजा सुना दी थी। हालांकि मुकदमे में इरफान को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत न मिलने के कारण इरफान अभी जेल में ही बंद हैं।

क्या बेटे से नहीं मिल सकता

पेशी पर ले जाते समय जब इरफान ने अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। उनकी हाथ पकड़ने को लेकर पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। बोले मेरा बेटा है...क्या मिल नहीं सकता।

2027 में साथ-साथ चुनाव लड़ेंगे

नसीम सोलंकी के विधायक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानपुर की जनता ने हमें जिताया है। यह जनता का प्यार है। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। 2027 का चुनाव हम दोनों साथ-साथ लड़ेंगे।

पैदल गश्त पर उतरीं एसपी श्रद्धा पाण्डेय

सुरक्षा का दिलाया भरोसा

» त्योहारों को लेकर कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

» संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल भ्रमण, यातायात पर कड़ा शिकंजा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। आगामी दुर्गापूजा और दशहरा पर्व के मद्देनज़र कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने मंगलवार को थाना अकबरपुर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ विशेष पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पैट्रोलिंग की और कई अहम दिशा-निर्देश दिए।एसपी ने साफ कहा कि सड़क पर अनधिकृत तरीके से खड़े वाहन, ठेले या गलत दिशा से आने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।पैदल भ्रमण के दौरान एसपी पाण्डेय ने आम लोगों से सीधा संवाद कर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा दिलाया। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को लगातार गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने पर जोर दिया। इसके साथ ही ओवरलोडिंग, सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग और वाहनों में अवैध बदलाव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

एसपी ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस काम में जनता का सहयोग भी बेहद अहम है।

ड्रोन वाले चोर का फर्जी शोर मचाने वाले 48 गिरफ्तार

माहौल बिगाड़ने वालों पर कानपुर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर शहर से लेकर गांव तक चोरों की फर्जी अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ विभिन्न थानाक्षेत्रों में पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर से लेकर गांव तक चोरों की फर्जी अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ विभिन्न थानाक्षेत्रों में पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

कानपुर पुलिस की कार्रवाई से शहर समेत ग्रामीण व सीमा से जुड़े क्षेत्रों में हड़कंप मचा रहा। क्षेत्रों में चोरों की अफवाह फैलाने व लोगों को भ्रमित करने में पुलिस ने मंगलवार को दिनभर अभियान चलाकर कार्रवाई की।

कानपुर के चकेरी एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में लगातार कई अराजकतत्व चोरों की अफवाह फैलाकर लोगों में भय के साथ

भ्रमित कर रहे हैं। जिसके चलते पुलिस ने मंगलवार 40 से ज?यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कानपुर पुलिस ने ऐसे क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया है। उनसे संवाद किया है। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि अपने घरों में रहें और भ्रामक खबरों से बचे।वहीं क्षेत्रीय जनता का इस पर कहना है कि उन्होंने कई बार चोरों को देखा है और उनको पकड़ने की कोशिश भी की है लेकिन आस पास में ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से चोर फरार हो जाते हैं।

डीसीपी बोले-संदिग्ध दिखे तो तत्काल दें सूचना

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि जिले के शहर व ग्रामीणों से अपील है कि वह किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में न लें। अगर कोई अंजान दिखाई दे तो उसकी पिटाई न करें। उससे बात करे और लगता है कि संदिग्ध है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस कार्रवाई करेगी और घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

मोदी जी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान एवं मिष्ठान वितरण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केशव मधुवन सेवा समिति द्वारा केशव मधुवन वाटिका में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ और मिष्ठान वितरण कर खुशी साझा की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व स्थानीय पार्षद आरती विजय गौतम ने किया।

समिति के महासचिव राजेन्द्र अवस्थी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी का जीवन देश के लिए समर्पित है और उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है।इस अवसर पर विजय गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, रोजगार, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ आतंकवाद, जातिवाद और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं।समारोह में प्रमुख रूप से राजेन्द्र अवस्थी, श्याम बिहारी शर्मा, राधा कृष्ण त्रिपाठी, नितिन गुप्ता, सौरभ शर्मा, अशोक अरोड़ा, वी.के. दीक्षित, कृष्ण मुरारी शुक्ला, बी.के. बाजपेई, बृज लाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

अकबरपुर नगर पंचायत की लापरवाही उजागर: कबाड़ में पड़ा शहर का पहचान बोर्ड

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अकबरपुर नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। नगर पंचायत द्वारा लगाया गया मुख्य लिंटर बोर्ड, जिस पर बड़े अक्षरों में अकबरपुर लिखा था और जो शहर की पहचान माना जाता था, अब टूटा-फूटा कबाड़ में पड़ा है। यह हाल कई दिनों से है, मगर जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने तक नहीं पहुंचे।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बोर्ड न केवल शहर की शान था, बल्कि प्रवेश करने वाले राहगीरों को अकबरपुर की पहचान कराता था।

लेकिन अब इसकी जर्जर हालत नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। व्यापारियों और राहगीरों ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर पंचायत सिर्फ कागजों पर सौंदर्यीकरण और विकास के दावे

» सौंदर्यीकरण के दावे खोखले साबित

» स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी,

करती है, जबकि सड़कों पर गंदगी, टूटी सड़कें और अब टूटा पड़ा यह बोर्ड उसकी नाकामी को उजागर कर रहा है।

लोगों ने चेतावनी दी कि टूटा पड़ा बोर्ड किसी भी समय हादसे का कारण बन सकता है। खुले पड़े बिजली के तार और लोहे की रॉड राहगीरों के लिए खतरा बने हुए हैं।

नागरिकों ने नगर पंचायत प्रशासन से तत्काल इस बोर्ड को ठीक कराने और शहर की सौंदर्यीकरण व्यवस्था को दुरुस्त करने

की मांग की है।

उनका कहना है कि अकबरपुर जैसे ऐतिहासिक नगर की पहचान कबाड़ में नहीं होनी चाहिए। यदि जिम्मेदार जल्द कार्रवाई नहीं करते तो जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है।

शिव मंदिर में प्रेमी युगल का विवाह: माला पहनाकर लिए सात फेरे

» परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किया था बरामद

» ग्रामीणों की मौजूदगी में संपन्न हुआ विवाह संस्कार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला चर्चा का विषय बन गया। मुर्रा ग्राम पंचायत के धर्मूपुर निवासी गयाप्रसाद की पुत्री अनीशा और युवक महेंद्र कुमार (पुत्र गिरीश) ने मलिखानपुर गांव के शिव मंदिर में एक-दूसरे को माला पहनाकर सात फेरे लिए और साथ जन्मों तक निभाने की कसमें खाईं। इस पावन क्षण के गवाह कई ग्रामीण भी बने।

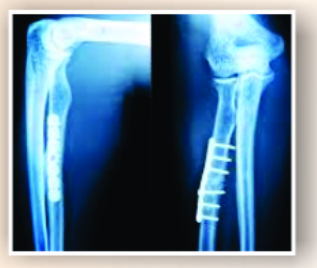

बता दें कि युवती के पिता ने पहले रसूलाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को महेंद्र बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने युवती को बरामद किया, लेकिन जब उसने बयान दिया तो स्पष्ट कहा कि वह अपनी इच्छा से महेंद्र के साथ रहना चाहती है। इसके बाद रिश्तेदारी में पहुंचे शिव मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया गया।इस घटना के बाद क्षेत्र में यह प्रेम विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं ग्रामीणों ने भी इसे आपसी सहमति का फैसला मानते हुए नवदम्पत्ति को आशीर्वाद दिया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 । **Email:** swarajindia2023@gmail.com । **Mob:** 7800009853, । **Website:** www.swarajindianews.com । (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

मिर्जा तालाब से अवैध खनन राजनीतिक दांवपेंच में उलझी कार्यवाही !

» नगर पंचायत अकबरपुर के ईओ और चेयरमैन पद गंभीर आरोप

4416 घन मीटर मिट्टी गायब - प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से दबा मामला!

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मत्स्य विभाग के सरकारी जलाशय मिर्जाताल अकबरपुर में मिट्टी के अवैध खनन का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि तालाब की अधिकांश भूमि से मिट्टी की खुदाई गैरकानूनी तरीके से कराई गई थी। सबसे गंभीर आरोप नगर पंचायत अकबरपुर पर है, जिसके जिम्मे खनन का खेल कराए जाने की बात सामने आई है।

जांच के अनुसार तालाब से लगभग 4416 घन मीटर मिट्टी गायब है। सवाल यह है कि यह मिट्टी आखिर गई कहां? किसने इसे बेचा और किसकी जेबें भरीं? नगर पंचायत अकबरपुर के अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार और चेयरमैन प्रतिनिधि जीतेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन सिंह पर सीधा संदेह जताया जा रहा है।

लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खनन अधिकारी अर्जुन कुमार कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं।सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में केवल नगर पंचायत ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है। रिपोर्ट को दबाकर और दोबारा जांच के नाम पर समय निकालकर जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी

इसी तालाब की खुदाई के नाम पर मिट्टी बेचने का आरोप है

मिर्जाताल की खुदाई में हुए इस बड़े घोटाले ने कानपुर देहात में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, इस मामले में खनन अधिकारी अर्जुन सिंह से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने उठाया सवाल

पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी व मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति ने कहा कि तालाब खुदाई की आखिर 4416 घन मीटर मिट्टी कहां गई?

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद कानपुर देहात।

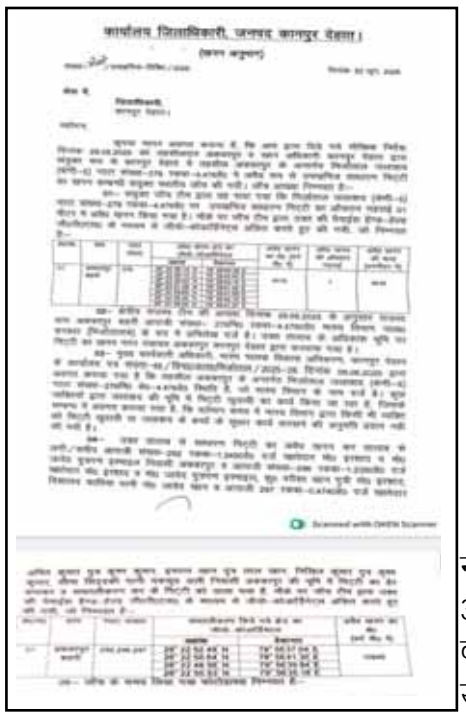

> **विरोधियों के द्वारा गलत और भ्रामक तथ्य प्रसारित किए गए थे, इसकी दोबारा जांच जिला प्रशासन के द्वारा कराई गई है। इसमें सारी चीज क्लियर हो गई है कोई अवैध खनन नहीं कराया गया है, पूरे नियमानुसार नगर पंचायत के द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं।**
> **जितेंद्र सिंह गुड्डन, चेयरमैन प्रतिनिधि**

तत्कालीन डीएम आलोक सिंह के द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट

खनन को लेकर पांच सदस्यीय जांच कमेटी एडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जांच आ गई है उसमें कुछ बिंदुओं पर अभी क्वेरी है, जिसको मैं करवा रहा हूं। मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी जो सही होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

नगर पंचायत अकबरपुर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जिला प्रशासन और खनन विभाग दबाव में हैं? भ्रष्टाचार की परतों को बचाने के लिए जांच को क्यों दबाया जा रहा है? सब लीपापोती हो रही है।

बरामदगी

गजनेर पुलिस की बड़ी कामयाबी

दो दिन से लापता नाबालिक बहनें सकुशल बरामद

» और सर्विलांस की मदद से मिली सफलता
»परिजनों से मिलते ही भावुक हुआ परिवार, पुलिस टीम की सराहना

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना पुलिस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए बीती रविवार से लापता दो नाबालिक सगी बहनों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घाटमपुर क्षेत्र से बरामद हुईं दोनों बच्चियों को देख परिजनों की आंखें खुशी से भर आईं और उन्होंने पुलिस टीम की खुलकर प्रशंसा की।

स्वराज इंडिया कानपुर देहात 09
दो दिन से लापता नाबालिग बहनें, पुलिस के हाथ अब भी खाली
जंगल में लकड़ियां बिनने गई दो मासूम बहनें लापता

मामला गजनेर थाना क्षेत्र के गांव रतवा मौजा नाही जूनिया का है। यहां के निवासी धर्मेंद्र कुमार की बेटियां लक्ष्मी (12) और प्रीति (7) रविवार सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने निकली थीं, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटीं। परिजनों की खोजबीन नाकाम रही तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सर्विलांस टीम व एसओजी की मदद से बच्चियों की तलाश तेज कर दी लगातार दो दिन की मशक्कत के बाद मंगलवार को पुलिस ने दोनों किशोरियों को घाटमपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्चियों को सुरक्षित लौटते देख परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों को सुरक्षित ढूंढ निकालना पुलिस टीम के लिए बड़ी राहत है।

सियासी तूफान

(अखिलेश यादव बनाम ओम प्रकाश राजभर...)

जन्मदिन से शुरू हुई '100 रुपये' वाली बयानबाज़ी, पहुंची सियासी तूफ़ान तक

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक अनोखे बयान से गरमा गई है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पुराने साथी और अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जन्मदिन पर तंज़ कसते हुए कहा - फ्अगर उनका जन्मदिन है तो मैं क्या करूं। अगर सौ रुपये से उनका काम चलता है तो भेजवा दें। हम हर किसी के जन्मदिन पर सौ रुपये ही देते हैं।

अखिलेश यादव के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बखेड़ा खड़ा कर दिया। जवाब में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखते हुए पलटवार किया और सपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए।

राजभर ने लिखा – समाजवादी पार्टी को सिर्फ पैसा दिखाई देता है। सत्ता में रहते हुए लूट-खसोट की जाती रही और अब जब साढ़े आठ साल से बाहर हैं तो 100 रुपये की बातें कर रहे हैं। सत्ता में रहते तो करोड़ों-अरबों से नीचे बात ही नहीं करते।

उन्होंने अखिलेश यादव पर जनता के पैसों से ऐश करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अखिलेश की शुभकामनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। राजभर ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए लिखा कि जनता के हित में काम करने वालों की शुभकामनाएं ही उनके लिए पर्याप्त हैं।

राजभर ने भावुक होते हुए लिखा – हमारे पास पैसा भले न हो, लेकिन ईमानदारी और जनता की सेवा का संकल्प है। अगर कभी अखिलेश यादव को बुरे वक्त में मदद चाहिए होगी तो हम अपने खेत की सब्ज़ी और अनाज ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति मदद करने की है, दिखावा करने की नहीं।

बयानबाजी के सियासी मायने

ओम प्रकाश राजभर का यह बयान केवल अखिलेश यादव पर हमला नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। सत्ता को कमाई का जरिया बताने वाले उनके शब्दों से विपक्ष को भी मौका मिल गया है। सवाल यह भी है कि जो राजभर कल तक अखिलेश के साथ गठबंधन में थे, क्या उन्हें तब सपा की कथित लूट-खसोट नहीं दिखी?

बीजेपी को हो रहा फ़ायदा?

अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच इस तनातनी ने भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। सपा-राजभर विवाद से विपक्षी एकजुटता की बजाय दरारें साफ़ दिख रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह बयानबाज़ी यूपी की राजनीति को और गरमाने वाली है। जन्मदिन से शुरू हुई यह नोकझोंक अब '100 रुपये' से आगे बढ़कर सत्ता, लूट और ईमानदारी की बहस में बदल चुकी है। आने वाले समय में यह टकराव भाजपा के लिए कितना मुफीद साबित होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया: अखिलेश यादव

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सपा चीफ ने दावा किया है कि चुनाव में मतदान वाले दिन बीजेपी फर्जी आधार कार्ड बनाती है और उसके बाद वोट डलवाती है. सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी ने प्रशासन का साथ लेकर के चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया.उन्होंने कहा कि फर्जी आधार बनाकर के बीजेपी ने फर्जी नामों के वोट अपने पक्ष में डलवा दिए. बीजेपी के पास कोई मशीन है जो चुनाव के दिन वो बूथ पर भेजते हैं. उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है. नकली आधार बनाकर वोट डाल देते हैं.कन्नौज सांसद ने दावा कहा कि एसएआर जो होने जा रहा है. एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है. आज अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो सरकार यही कहेगी कि एसएआर इसलिए कर रहे हैं. अपने कार्यकर्ताओं से सपा चीफ ने कहा कि मजबूत बूथ लेवल एजेंट बनाएं.आपको अपना वोट बनाना है, वोट बचाना है उसके बाद घोटाले से बचना है.

यूपी के महापौरों के अधिकारों पर लग सकती है रोक!

» नगर विकास विभाग की समीक्षा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी

» अवस्थापना मद से होने वाले कामों में लेटलतीफी होने पर मेयर के अधिकारों पर दोबारा विचार करने के संकेत दिए

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। सीएम योगी ने नगर विकास विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए अवस्थापना मद से होने वाले कामों में लेटलतीफी होने पर मेयर के अधिकारों पर दोबारा विचार करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर बजट का समय से सही इस्तेमाल करना होगा ताकि पारदर्शिता के साथ काम हो और प्रॉजेक्टों में अनावश्यक तरीके से देरी न हो। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा न होने पर मेयरों के अधिकारों पर दोबारा विचार करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने सभी नगर निगमों में ईईएसएल का बकाया भुगतान तुरंत करने का निर्देश भी दिया।सूत्रों की मानें तो लखनऊ समेत कई नगर निगमों में अवस्थापना मद के बजट से होने वाले कामों में समय से काम न होने और भुगतान में लेटलतीफी की शिकायतें मिल रही थीं। कुछ नगर निगमों में मेयर और नगर आयुक्तों के बीच सहमति न बनने और विवाद की स्थिति होने की शिकायतें भी सामने आ रही थी। ऐसे में सीएम की इस टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है।

30 तक कार्ययोजना सौंपेगा पीडब्ल्यूडी

सीएम योगी की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि रेस्टोरेशन एवं विशेष मरम्मत के लिए 2,750 किमी सड़कें चिह्नित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसमें 62.99त्न प्रगति दर्ज की है। वहीं, नगर विकास विभाग ने 35.50त्न और अवसंरचना व औद्योगिक विकास विभाग ने 48.77त्न का इजाफा होने का दावा किया है। सीएम ने सभी विभागों के दावों को सुनने के बाद 30 सितंबर तक सर्वे कर कार्ययोजना देने को कहा है। लोक निर्माण विभाग को सर्वे और कार्ययोजना तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा।

राज्यपाल से भी बड़ा सदर तहसील का लेखपाल?

» रिश्वत का सौदा लिखित रिपोर्ट में ओवरराइटिंग

» अफसरशाही की मिलीभगत या चुप्पी,किसकी रखवाली कर रही सदर तहसील

» रामराज्य की नगरी में रामपथ चौड़ीकरण बना भ्रष्टाचार का चौराहा

» सारे आरोप निराधार-लेखपाल

» सदर तहसील के लेखपाल पर 10 हजार रिश्वत न मिलने पर अपात्र घोषित करने का आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामराज्य की धरती पर एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास और जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सदर तहसील का लेखपाल अंजनी कुमार शुक्ला भ्रष्टाचार का नया साम्राज्य खड़ा कर चुका है। पीड़ित दुकानदार ने लेखपाल पर 14000 रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। शहर में विकास के नाम पर चल रही पुनर्वास योजना उसके लिए वसूली का अड्डा बन गई है।

रामपथ चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की प्रक्रिया में लेखपाल ने गरीबों के आंसुओं को अपनी कमाई का साधन बना लिया। एक दुकानदार, जिसकी पत्नी और स्वयं की दो दुकानें टूटीं, उसे केवल एक दुकान देकर अपात्र करार दिया गया। वहीं एक अन्य लाभार्थी परिवार को पत्नी और बेटों के नाम पर तीन-तीन दुकानें दिलवाई गईं। यह भेदभाव भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या का स्पष्ट उदाहरण है।

का प्रार्थना पत्र ही वापस कर दिया। सवाल यह है कि जब तहसील स्तर पर ही आदेश की ऐसी धज्जियां उड़ रही हों, तो अफसरों की कुर्सी किस काम की?पीड़ित का कहना है कि 2 जनवरी 2025 को पीड़ित का पुनर्वास आवेदन पात्र बताया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि लेखपाल ने बदले में 14,000 की रिश्वत माँगी। मजबूर दुकानदार ने 4,000 देकर कहा साहब, मेरे पास और देने को नहीं है। लेखपाल ने शेष 10,000 की चार महीनों तक प्रतीक्षा की। जब रकम नहीं मिली, तो 7 अप्रैल 2025 को वही रिपोर्ट उठाई और पात्र शब्द के आगे 'अ' जोड़कर उसे 'अपात्र' बना दिया। यह ओवरराइटिंग तहसीलदार के हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में साफ दिखाई देती है जो भ्रष्टाचार की जीवंत गवाही है।

चार महीने से अधिक समय बीत चुका है। पीड़ित दुकानदार अब भी तहसील और अफसरों के दरवाज़ों पर न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन नतीजा रामराज्य में भी कोई सुनने वाला नहीं।

सारे आरोप निराधार-अंजनी शुक्ला लेखपाल

उक्त आरोपो के सम्बंध में जब आरोपी लेखपाल अंजनी शुक्ल का कहना है कि आरोप निराधार है। हमे सरकार वेतन देती है किसी के दो चार हजार देने से मैं करोड़पति नही हो जाऊंगा। जहां तक बात रही आवेदन में अपात्र होने की आख्या लगाने की तो जो सही होगा उसे ही हम पात्र लिख सकते। जो गलत होगा उसे तो अपात्र ही लिखेंगे। मैंने कोई फ़ाइल नही वापस किया है। मेरा हल्का बदल गया है। जिसने किया वापस वह जाने। जिनको लाभ नही मिलता वह ऐसे आरोप लगाते ही है।

जिला प्रशासन के आदेश की धज्जियां

जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने एक सप्ताह में पीड़ित को दुकान आवंटित करने के आदेश दिए। विकास प्राधिकरण को निर्देश भी जारी हुए। लेकिन लेखपाल ने आदेश को ठेंगा दिखाते हुए पीड़ित

स्वराज इंडिया सवाल करता है

-क्या सदर तहसील का लेखपाल अफसरों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल कर सकता है?

-जब जिलाधिकारी का आदेश ही एक लेखपाल के आगे बेअसर हो जाए, तो सिस्टम की ताकत किसके लिए है?-क्या अयोध्या का विकास जनता के लिए है या भ्रष्टाचारियों की तिजोरी भरने के लिए?

100 कॉल्स का खेल, फंस गए ख़ाकीवाले

» जेल में निरुद्ध राजा मान सिंह कनेक्शन में फंसे अफसर

» जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर से 100 बार बात करने पर सस्पेंड हुए एसएचओ

» मामले के लीपापोती में नपे सीओ अयोध्या

एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी का कार्यक्षेत्र बदल दिया और पूरा कलंदर थाने के एसएचओ देवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया।

जांच में पाया गया कि एसएचओ देवेंद्र सिंह की जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर और सपा जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह से लगातार संपर्क था। रिपोर्ट के अनुसार, देवेंद्र सिंह ने राजा मान सिंह से 100 से ज्यादा बार फोन पर बात की, जिनमें कई कॉल 5 से 8 मिनट तक चलीं।इसी मामले में सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि उन्होंने मामले में लीपापोती की। इस पर नाराज होकर एसएसपी ने उन्हें अयोध्या जैसे संवेदनशील क्षेत्र से हटाकर सीओ यातायात (यलो जोन और कानून व्यवस्था) की जिम्मेदारी दे दी।

अयोध्या में राजेश सिंह मानव पालिका कर्मचारियों के भगीरथ

» राजेश सिंह मानव-जब एक बाहरी व्यक्ति बने नगर पालिका कर्मचारियों के मसीहा

» मानव ने 22 साल पहले भ्रष्टाचार के दलदल से उठायी आवाज़

» सूदखोरों के शिकंजे से कर्मचारियों को निकाला बाहर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।कभी फैज़ाबाद नगर पालिका की गलियाँ सिर्फ़ कूड़े से ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की बेबसी और आहों से भी अटी रहती थीं। यह वह समय था जब पेंशन की आस में बुज़ुर्ग कर्मचारी भीख मांगते देखे जाते थे, जब सफ़ाईकर्मी सूदखोरों की गिरफ्त में जकड़े रहते थे और जब वेतन का कैश 180 दिन तक सिमटकर रह जाता था। हर तरफ़ भ्रष्टाचार का जाल था, और कर्मचारी अपनी ही संस्था में गुलाम से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर। ऐसे हालात में जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब मंच पर आए एक ऐसे व्यक्ति, जो खुद पालिका कर्मचारी भी नहीं थे राजेश सिंह मानव।

18 अगस्त 2003 अयोध्या के ऐतिहासिक तिलक हाल में शपथ का ऐसा दृश्य रचा गया, जिसने नगर पालिका कर्मचारियों के भविष्य की दिशा बदल दी। स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे—राजेश सिंह मानव। कर्मचारियों ने उन्हें अपने बीच से नहीं, बल्कि बाहर से बुलाया। कारण साफ़ था भीतर का हर कर्मचारी विभागीय दबाव में बंधा हुआ था। लेकिन मानव का क़द उस दबाव से ऊपर था।

तेरह साल का काला अध्याय

मानव के सामने समस्याओं का अंबार था। तेरह वर्षों से अटका ढाई करोड़ का जीपीएफ़ फंड, जिसे तत्कालीन अध्यक्षों ने बंदरबांट कर लिया था।

हज़ारों सफ़ाईकर्मियों को 300 दिन की जगह केवल 180 दिन का कैश वेतन मिलता। वर्दी, साइकिल भत्ता, चयन-ग्रेड, पदोन्नति—सब अधर में लटके। मृतक आश्रित नियुक्ति, ओवरटाइम और पेंशन भुगतान तो जैसे केवल किताबों में दर्ज नियम रह गए थे। नगर पालिका की संपत्तियाँ औने-पौने दामों पर बेच दी जातीं, कबाड़ चोरी कर बेंच दिया जाता और कर्मचारियों का हक़ नेताओं की जेबें भरता।

राजेश सिंह मानव ने एक-एक करके इस भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ीं। 7 जुलाई 2003 को मण्डलायुक्त को लिखा गया पत्र कर्मचारियों के जीवन का टर्निंग प्वाइंट बना। आदेश हुआ कि हर कर्मचारी का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले और वेतन सीधे उसमें जाए। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुँचाई गई शिकायत पर जिलाधिकारी को जाँच बैठानी पड़ी। जीपीएफ़, पेंशन और वर्दी जैसे मुद्दे कर्मचारियों की जुबान से निकलकर शासन के गलियारों तक पहुँचे।

मानव ने खुलासा किया कि तत्कालीन पालिका अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कर्मचारियों का एलआईसी बीमा केवल कमीशन खाने के लिए कराया था, पर कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन इस पर आज बोलने वाला कोई नही है।

आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो यह साफ़ झलकता है कि अगर 2003 में मानव ने मोर्चा न संभाला होता तो पालिका कर्मचारी अब भी उस अंधकार में जकड़े रहते। उन्होंने यह साबित कर दिया कि आंदोलन की असली ताक़त पद या स्थिति में नहीं, बल्कि नीयत और हिम्मत में होती है।नगर पालिका का इतिहास उन्हें फ़कर्मचारियों का उद्धारकफ़ कहे बिना अधूरा रहेगा।

अनुदेशकों को 17 हजार मानदेय दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

ऑर्डर हुआ रिजर्व, अनुदेशकों को सकारात्मक फैसले की उम्मीद

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। उत्तर प्रदेश के 25 हजार अनुदेशकों के 17 हजार रुपए मानदेय के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को करीब 3 घंटे चली लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जब पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया-

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे और कहा जब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट के सुझाव पर सहमति जताई।

2017 में हुआ था मानदेय दोगुना-

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 2017 में 8,470 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद इसे लागू नहीं किया गया। इसके खिलाफ अनुदेशकों ने लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट में दो साल बाद बहस पूरी-

करीब 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सखाराम यादव, पी.एस. पटवालिया और दुर्गा तिवारी ने अनुदेशकों का पक्ष रखा। मुख्य याची राकेश पटेल और अनुराग भी मौजूद रहे। अनुदेशकों के विधिक सलाहकार बृजेश त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अनुदेशकों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बेंच ने संकेत दिए कि जल्द ही विस्तृत आदेश पास किया जाएगा। अनुदेशकों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें 17,000 रुपए मानदेय का लाभ दिलाएगी।

लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश और राज्य सरकार की अपील-

लखनऊ की सिंगल बेंच के तत्कालीन जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 9फीसदी ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील में गई। डबल बेंच ने केवल एक साल का 17,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था।

साड़ी बदलने वाले एआई ट्रेंड' में छुपे हैं कई खतरे, नई तकनीक से रहे सावधान!

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड धूम मचा रहा है। गूगल जेमिनी (Google Gemini) ·Ô¤ Nano Banana टूल के जरिए लोग अपनी साधारण सेल्फी को कुछ ही सेकंड्स में 90 के दशक की बॉलीवुड हीरोइन जैसा लुक दे रहे हैं। महिलाएं अपनी तस्वीरों को काली पार्टी वियर साड़ी, पोल्का डॉट्स वाली चिफॉन या लाल साड़ी में बदलकर इंस्टाग्राम-फेसबुक पर धड़ाधड़ पोस्ट कर रही हैं। ये ट्रेंड मजेदार जरूर है, लेकिन इसके खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह यह एआई आपकी फोटो में कपड़े बदल सकता है, उतनी ही आसानी से अनुचित एडिट्स भी कर सकता है। यानि जो पहनाता है, वो उतार भी सकता है। ब्लैकमेलिंग और साइबरबुलिंग

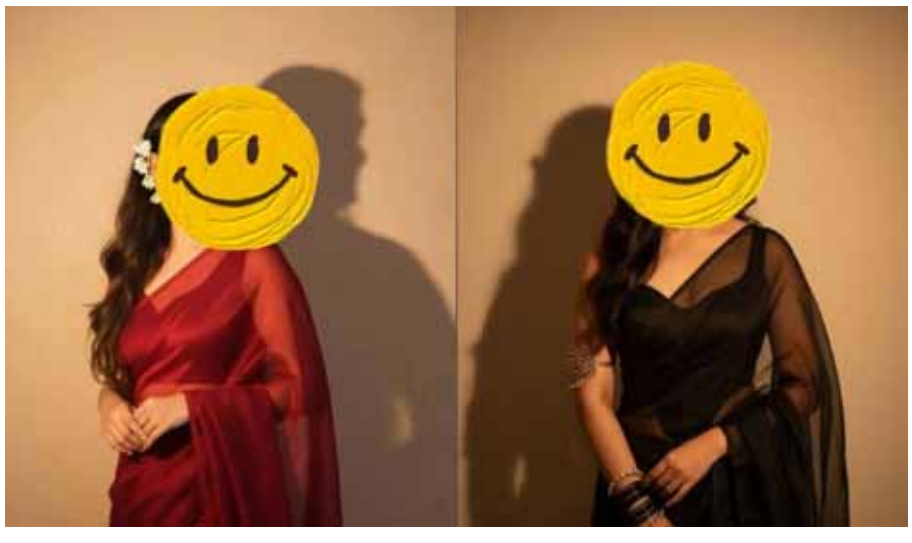

के मामलों में इस्तेमाल संभव। डार्क वेब या पोर्न साइट्स पर बिना सहमति के फोटो वायरल हो सकती है।राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर गलत सूचनाएं फैलाने में भी उपयोग। फोटो को अनुचित पोज़ या कपड़ों में बदला जा सकता है।

प्राइवेसी का बड़ा खतरा

फोटो अपलोड करने पर डेटा कंपनियों के सर्वर तक पहुंच जाता है। भले ही कंपनियां डिलीट करने का दावा करती हों, लेकिन हैक या लीक होने पर निजी जानकारी बाहर जा सकती है। एआई टूल्स आपकी उम्र, जेंडर, लोकेशन और यहां तक कि चेहरे की पहचान जैसी जानकारियां भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।

क्या करें सुरक्षित रहने के लिए?

सार्वजनिक रूप से अपनी निजी फोटो अपलोड करने से बचें। ऐप्स और वेबसाइट की डेटा पॉलिसी जरूर पढ़ें। प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर फोटो क्रॉप करें। अपनी फोटो अनजान लोगों को शेयर न करें।रेट्रो वाइब्स का ये ट्रेंड भले ही मजेदार लगे, लेकिन याद रखिए एआई एक दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए हो सकता है, लेकिन जरा सी लापरवाही इसे खतरे में बदल सकती है।